



सांध्य दैनिक 4PM



अगर आपके लहू में रोष नहीं है, तो ये पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या मतलब अगर वो मातृभूमि के काम ना आए।

-चंद्रशेखर आजाद

जिद...सच की

www.4pm.co.in | www.facebook.com/4pmnewsnetwork | @Editor_SanjayS | YouTube | 4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 12 ● अंक: 73 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शनिवार 18 अप्रैल, 2026

मूल्य
₹ 3/-

जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी... 7 बिहार में सम्राट की राह नहीं होगी... 3 11 साल के अनुभव बताता है भाजपा... 2

बैकडोर एजेंडा ध्वस्त

धुआं-धुआं रणनीति अजेय छवि चकनाचूर

» संविधान संशोधन विधेयक खारिज
» कांग्रेस ने बताया विपक्ष की जीत, कहा- महिला आरक्षण पर समर्थन अटूट

131वां

संविधान संशोधन बिल 2026 लोकसभा में पास नहीं हो पाया।

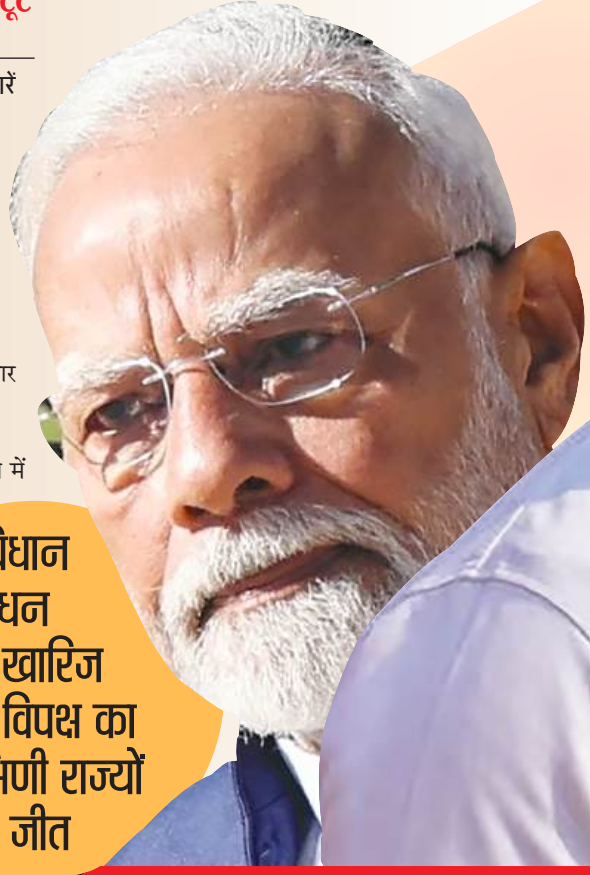
इंदिरा के पोते ने कर दिया कमाल जो कहा वह करके दिखाया नहीं पास होने दिया विधेयक

संशोधन या संविधान का पुनर्लेखन

विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यही रहा कि यह विधेयक संशोधन के नाम पर पुनर्लेखन का प्रयास था। सवाल उठाना गया कि क्या सरकार धीरे धीरे संविधान की मूल भावना को बदलने की दिशा में काम कर रही है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि संविधान में हर संशोधन सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं होता वह सत्ता और जनता के बीच के रिश्ते को भी परिभाषित करता है। और जब यह रिश्ता एकतरफा होने लगे तो लोकतंत्र का संतुलन डगमगाने लगता है। विपक्ष के नेताओं ने संसद के भीतर और बाहर एक ही बात दोहराई कि यह विधेयक जनता के अधिकारों को सीमित करने और राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करने की कोशिश थी। क्या यह अतिशयोक्ति थी या सचमुच कोई गहरी परत थी जिसे सरकार खुलकर सामने नहीं लाना चाहती थी?

12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ

कल की शाम भारत के संसदीय इतिहास में एक बड़े उलटफेर की गवाह बनी। मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया 131वां संविधान संशोधन बिल 2026 लोकसभा में पास नहीं हो पाया। पिछले 12 सालों में यह पहला मौका है जब मोदी सरकार का कोई संविधान संशोधन बिल सदन में गिरा हो। दो दिनों तक कल लंबी बहस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों के बावजूद सरकार जरूरी आंकड़ों का जुगाड़ नहीं कर पाई। सदन में वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े जबकि विरोध में 230 सदस्यों ने बदन दबाया। पिछले 12 सालों में यह पहली बार देखा गया कि विपक्ष ने इतनी सटीक रणनीति के साथ सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव और मनमोहन बजाज जैसे दिग्गज नेताओं के बीच हुए बेहतर तालमेल ने सरकार के रणनीतिकारों को चौंका दिया। विपक्ष ने एक सुर में पार्लियामेंट को चुनावी नक्शा बदलने की साजिश बताकर वोटिंग में सरकार को पछाड़ दिया।



संविधान संशोधन विधेयक खारिज होने पर विपक्ष का दावा दक्षिणी राज्यों की जीत

सरकार की चुप्पी रणनीति या स्वीकारोक्ति?

विधेयक के खारिज होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर हुई। न कोई तीखा पलटवार न कोई आक्रामक बयान बस एक नियंत्रित संतुलित चुप्पी। लेकिन राजनीति में चुप्पी भी बोलती है। सरकार की चुप्पी पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह चुप्पी एक रणनीतिक विराम है?

या फिर एक ऐसी स्वीकारोक्ति जिसे शब्दों में ढालना मुश्किल हो रहा है? क्योंकि अगर यह विधेयक इतना ही जनहितकारी था जैसा कि दावा किया जा रहा था तो उसके खारिज होने पर सत्ता की बेचैनी साफ दिखनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं सरकार की तरफ से जो दिखा वह एक

अजीब सी टंडक दिखाई दी। सरकारी चुप्पी पर और भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने जनबुझकर हार स्वीकार की है। क्या इसमें भी कोई रणनीति और राजनीतिक चाल है क्योंकि राजनीति में हार कर भी बाजी जीती जाती है।
संबंधित खबरें पेज 8 पर



11 साल के अनुभव बताता है भाजपा भरोसा करने लायक नहीं: अखिलेश

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकसभा में तीन विधेयकों पर चर्चा के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि मानों सहमति बन गई है लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने सदन का पूरा माहौल बदल दिया। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी लिख कर दे कि महिला पीएम बनाएंगे तब भी समर्थन नहीं करेंगे। कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि 11 साल के जो अनुभव रहे, अगर बीजेपी ये लिख कर दे देगी कि हम महिला पीएम बनाएंगे तब भी इनका भरोसा नहीं करेंगे।

दरअसल, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष बताए क्या बिल पारित करने के लिए सहमत हो? सरकार 50 प्रतिशत सीट बढ़ाने के लिए तैयार है।

» बोले सपा प्रमुख- बीजेपी लिख कर दे कि महिला पीएम बनाएंगे तब भी समर्थन नहीं करेंगे

प्रदर्शन के लिए कम से कम 12 महिलाओं को तो भेजती भाजपा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय पर प्रदर्शन को लेकर कहा कि भाजपा वाले लगभग 12 करोड़ महिलाओं वाले उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 12 महिलाओं को तो भेजते।

घंटा दीजिए हम संशोधन कराने के लिए तैयार हैं, हमें 50 प्रतिशत सीट बढ़ानी ही हैं, हमें कोई चोरी नहीं करनी है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और सांसद केशी वेणुगोपाल ने कहा था कि सरकार लिखकर दे कि सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटें बढ़ेंगी और 2026 के जनगणना के आधार पर परिसीमन हो।

इसके जवाब में शाह ने कहा कि हम लिखकर देने को तैयार हैं कि सीटें 50 फीसदी बढ़ेंगी लेकिन हम 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के मांग के झांसे में नहीं आने वाले।

अखिलेश के इस जवाब के बाद गृह मंत्री ने कहा कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण बिल गिर जाएगा लेकिन इस देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन है? चुनाव में माताएं हिसाब मांगेंगी, भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। शाह ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण के नाम पर भी भ्रम फैला रहा है भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। गृह मंत्री ने कहा कि इंडिया अलायंस तुष्टीकरण के कारण ऐसी बात करता है। संविधान के किस आर्टिकल के हिसाब से आप धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे? धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना देंगे ना किसी को देने देंगे।

अपर्णा यादव का विस पर प्रदर्शन, सपा और कांग्रेस का झंडा जलाया

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई। अपर्णा यादव ने विधानसभा के सामने सपा और कांग्रेस का झंडा जलाकर विरोध जताया। संसद में महिला आरक्षण बिल पारित न हो पाने को लेकर सियासत तेज हो गई है।

राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने विधानभवन के सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित इस बिल के पास न होने से महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अपर्णा ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण महिला आरक्षण बिल अटका हुआ है। उधर, राज्य महिला आयोग की सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया। महिला आयोग की ओर से इस मामले में शनिवार को बड़ा प्रदर्शन करने की बात भी कही गई है।



सीएम सम्राट चौधरी से मिले नीतीश कुमार

मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली, राजनीतिक स्थिति और सरकार के कामकाज पर चर्चा

4पीएम न्यूज नेटवर्क

पटना। बिहार की राजनीति में हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली, जिसमें देश और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई।

15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह पहली बार है जब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार आमने-सामने मिले। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र यादव से भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात की तस्वीरें सम्राट चौधरी ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर साझा कीं। तस्वीरों में नीतीश कुमार सहज और प्रसन्न नजर आए। यहां तक कि उन्होंने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर आत्मीयता भी दिखाई। सम्राट चौधरी ने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मुलाकात के बीच राज्य की शराबबंदी नीति भी चर्चा के केंद्र में रही। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से जारी



अनंत सिंह समेत कई नेताओं ने उठाए सवाल

इधर, मोकामा से जदयू विधायक लगातार शराबबंदी खत्म करने की मांग उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि प्रतिबंध के बावजूद लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। और इसके स्थान पर अन्य खतरनाक नशों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे समाज पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कई अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं, जिससे राज्य में शराबबंदी को लेकर बहस तेज हो गई है।

रहेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच का

हिस्सा है और प्रधानमंत्री भी इस पहल की सराहना कर चुके हैं।

27 के विधानसभा चुनावों के चलते भाजपा करवा रही छापेमारी: मान

» उपचुनाव में हार का बदला ले रही बीजेपी

4पीएम न्यूज नेटवर्क

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग की छापेमारी के जरिए विपक्ष को परेशान करके 27 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू करने का आरोप लगाया। मान ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को निशाना बनाकर की गई हालिया ईडी कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने बताया कि ईडी ने हाल ही में राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर छापे मारा था, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, जहां 35 से अधिक देशों के हजारों छात्र पढ़ते हैं।

मान ने कहा कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे आम आदमी पार्टी से हैं। ईडी संजीव अरोड़ा के घर पर छापे मार रही है। उन्होंने यहां उपचुनाव में भाजपा को हराया था। आज वे निशाने पर आ गए हैं। अरोड़ा पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के उन नेताओं में से एक हैं जिन पर ईडी ने छापे मारा है। मान ने कहा कि ये कार्रवाइयां 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की तैयारियों का हिस्सा हैं। आबकारी नीति मामले पर बोलते हुए उन्होंने जोर दिया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय



संयोजक अरविंद केजरीवाल और नेता मनीष सिसोदिया को अदालत ने बरी कर दिया क्योंकि मामला मनगढ़ंत था, जिसके परिणामस्वरूप कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ।

भगवंत मान ने कहा कि इसका मतलब है कि भाजपा ने 27 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने ईडी और आयकर विभाग को भेजना शुरू कर दिया है और विपक्ष को डराना-धमकाना शुरू कर दिया है। भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए 117 लोग नहीं मिल रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है; मैं इसकी निंदा करता हूं। केवल गैर-भाजपा सरकारों को ही फंसाया जा रहा है। छापों से कुछ भी हासिल नहीं होता। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया गया। एक मनगढ़ंत मामले के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने का कोई तरीका नहीं था। अगर कोई उनके सामने झुकता है, तो वह पूरी तरह से बरी हो जाता है।



बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

बसपा तोलमोल कर करेगी प्रत्याशियों का चयन

» एसआईआर की सूची के आधार पर बसपा बनाएगी रणनीति

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। विस चुनाव 27 के लिए बसपा टोकबजाकर ही कोई फैसला करेगी। सूत्रों के अनुसार बसपा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान से हुए फायदे-नुकसान का आकलन कर रही है। बहुजन समाज पार्टी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) से हुए नफा-नुकसान को भांप रही है।

पार्टी ने हाल ही में गठित की गई 15 हजार बूथ कमेटियों से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि बसपा ने इस अभियान में



सक्रिय रूप से भाग लिया था ताकि उसके समर्थकों का नाम मतदाता सूची में बरकरार रहे।

पार्टी सूत्रों की मानें तो एसआईआर अभियान में जिन पदाधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई, उन्हें टिकट चयन में तक्जो दी जाएगी। खासकर जिलों में जिन संभावित प्रत्याशियों को प्रभारी बनाया गया था, उनके बारे में रिपोर्ट मिलने के बाद उनकी दावेदारी

पर फैसला लिया जाएगा। बसपा सुप्रिमो मायावती खुद इस मामले की गहनता से समीक्षा कर रही हैं। उन्होंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से इस बाबत सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाने को कहा है। खासकर पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या कम होने के बारे में बताने को कहा गया है ताकि जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल होने से रह गए हैं, उनको आगे जुड़वाया जा सके। बता दें कि बसपा सुप्रिमो ने बीती 7 फरवरी को राजधानी में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में एसआईआर के कार्यों में विशेष रुचि दिखाने का निर्देश दिया था। उन्होंने बहुजन समाज को जागरूकता दिखाते हुए इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की थी।

बिहार में सम्राट की राह नहीं होगी आसान

राज्य की बदहाली दूर करना सबसे बड़ा काम

- » विपक्ष के साथ अपनों से मिलेगी चुनौती
 - » सहयोगी जट्टय, चिराग का भी रहेगा दबाव
 - » राजद-कांग्रेस व अन्य भी रखेंगे कड़ी नजर
- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। आखिरकार बिहार में भाजपा का सीएम मिल गया। सम्राट चौधरी वहां पर मुख्यमंत्री होंगे। पर क्या उनके लिए आगे की राह आसान होगी ये कहना जलदबाजी होगी। जट्टय के दिग्गज नेता नीतीश कुमार की छवि के सामने उनकी छवि कमतर है। सबसे बड़ी बात जट्टय सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानने वाली पार्टी है जबकि भाजपा कोर हिंदुत्व की राजनीति करती है ऐसे में आने वाले समय में दोनों के बीच ऐसे मुद्दों पर टकराहट होने के आसार है। आने वाले समय में देखना होगा की नए सीएम अपने सहयोगियों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें केवल सहयोगियों से चुनौती मिलेगी उन्हें अपनी पार्टी के अंदर भी विरोध या गुटबाजी झेलनी पड़ सकती है।

सबसे बड़ी बात नीतीश की जनता के बीच में स्वीकार्यता व लोकप्रियता उसके बराबर क्या वह जनता के मन में जगह बना पाएंगे। इसके अलावा बिहार की तरक्की व खुशहाली की क्या योजना रहेगी ये सब भी देखने वाला होगा। वहीं विपक्ष के निशाने पर भी हो होंगे। क्योंकि उनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पीके व तेजस्वी उन पर अभी से हमलावर हैं। कुल मिलाकर बिहार के नए सम्राट को फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज मिला है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, या पूर्व मुख्यमंत्री दम्पति लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, कभी भी चैन पूर्वक राज नहीं कर सके। लिहाजा, मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी उन जातीय और साम्प्रदायिक चुनौतियों से जूझना होगा, जो बिहार के विकास में शुरू से ही बाधक समझी गई हैं। लेकिन जिस प्रकार से आधुनिक बिहार के निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा को कांग्रेस के सहयोग से लंबे समय तक राज करते हुए जनसेवा का मौका मिला, वैसी ही मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भाजपा के सहयोग से जनसेवा का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा भी है कि पार्टी ने उन्हें पद नहीं, जनसेवा का अवसर दिया है, इसलिए विकास, सुशासन और समृद्धि उनके शासन का मूलमंत्र होगा। बिहार में 26 साल पहले हुए राज्य विभाजन के बाद औद्योगिक आधार छोटा हुआ है, क्योंकि अधिकांश बड़े उद्योग-धंधे झारखंड के हिस्से में चले गए। तत्पश्चात छोटे और कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग तकनीकी पिछड़ेपन और वित्तीय अभाव के कारण इनका समग्र विस्तार नहीं हो पा रहे हैं।



नीतीश कुमार ने बिहार को दिया नया आकार

बिहार के विकास में श्रीकृष्ण सिन्हा के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ी रेखा खींचने की कोशिश की, प्रगति नजर भी आई, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश के विकास को देखा जाए तो अब भी बिहार के विकास में कई बड़ी बड़ी चुनौतियाँ बाकी हैं, जो आंकड़ों और राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखने पर साफ दिखती हैं। इसलिए भाजपा की सरकार के सुलझे हुए और समावेशी प्रवृत्ति वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी बिहार के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित चुनौतियों से जूझना होगा। लेकिन अपने मृदु स्वभाव से वे एक एक करके इनसे पार पा जाएंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है।

बुनियादी ढांचा और शहरीकरण में निवेश

बिहार में सड़क नेटवर्क, बिजली, जल सुविधा, नालियाँ, जनस्वास्थ्य और शहरी बुनियादी ढांचा अभी भी प्रमुख रूप से कमजोर जगह बनी हुई है। चाहे स्थापित

शहर हों या कस्बाई शहर, यहां शहरीकरण बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिससे औद्योगिक सेवा अर्थव्यवस्था को उतना बल नहीं मिल पा रहा जितना दूसरे विकसित

राज्यों में मिला है। इसलिए नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि रोजगार के सृजन में इस क्षेत्र का बड़ा होता है।

कृषि व उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देना होगा



कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के चलते उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देना होगा ध्यान यद्यपि बिहार की आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन उत्पादकता और आय दोनों ही अपेक्षाकृत कम हैं। ऐसा इसलिए कि उत्तर बिहार 4 महीना बाढ़ से आक्रांत रहता है और तभी दक्षिण बिहार सूखा से जूझ रहा होता है। खेती और बागवानी यहां पर होती तो है, लेकिन भंडारण सुविधाएँ, बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और बारहमासी सिंचाई की सीमित पहुंच जैसे कारकों के कारण कृषि अभी भी बहुत जोखिम भरी और कम लाभ वाली साबित होती है। लिहाजा किसानों और मजदूरों के बच्चे परदेश कमाने चले जाते हैं और अपनी उद्यमिता से सबको सुख पहुंचाते हैं।

बिहार को चुनौतियों से बाहर निकालना होगा टॉस्क

पहला, निर्धनता, रोजगार और मानव पूंजी के नजरिए से विकास आंकड़े बताते हैं कि बिहार, भारत के सबसे कम आय वाले राज्यों में शुमार है, जहां गरीबी दर अभी भी काफी ऊँची है और रोजगार की गुणवत्ता कमजोर है। समझा जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य

के क्षेत्र में निवेश कम होने के कारण यहां की मानव पूंजी कमजोर है- साक्षरता और स्किल लेवल अभी



भी देश के स्तर से काफी नीचे हैं, जिससे युवाओं को अच्छे रोजगार के अवसर मिलने में दिक्कत होती है। ऐसे में यदि अपराध, जातीय सोच और सांप्रदायिक

मिजाज को हतोत्साहित करके इन लक्ष्यों को पाया जा सकता है। इसके लिए अप्रवासी बिहारियों और बिहार मूल के एनआरआई को आकर्षित करने वाली योजनाओं को बनाना होगा और उनपर दृढ़तापूर्वक अमल करना होगा।

औद्योगिक विकास पर ध्यान देना होगा

बिहार में राज्य विभाजन के बाद औद्योगिक आधार छोटा हुआ है, क्योंकि अधिकांश बड़े उद्योग-धंधे झारखंड के हिस्से में चले गए। तत्पश्चात छोटे और कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग तकनीकी पिछड़ेपन और वित्तीय अभाव के कारण इनका समग्र विस्तार नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति को बदलना होगा। इस कारण और निजी निवेश की दृष्टि से बिहार अभी भी निवेश

अनुकूल राज्यों की पहली पंक्ति में नहीं है, बल्कि तेजी के साथ उद्योग बढ़ाने की चुनौती बरकरार है। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को चाहिए कि वह महाराष्ट्र और गुजरात की तर्ज पर बिहार-उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति तेज करे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में औद्योगिक रफ्तार तेज होने से लुक ईस्ट की विदेश नीति को मजबूत आधार मिलेगा।

जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाएँ बेहतर करना

बिहार के शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएँ बेहद कमजोर हैं- खासकर डॉक्टर आबादी अनुपात कम, स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है और कुपोषण जैसी समस्याएँ अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। इसी

तरह पीडीएस राशन, योजनाओं के वितरण में धांधली, रिसाव और कार्यान्वयन की कमजोरी विकास के लाभों को गरीबों तक पहुँचने से रोकते हैं। इस स्थिति में अमूलचूल बदलाव लाना होगा, ताकि स्थिति बदले।

तेजस्वी यादव बोले- सीएम, बिहार को बदहाली से निकाले



नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, सम्राट चौधरी द्वारा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बधाई तथा मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि नए माननीय मुख्यमंत्री जी इस कड़वे,

अग्रिय एवं कठोर तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत होंगे कि वर्षों के शासन उपरांत भी नीति आयोग के अधिकांश मानकों, सतत विकास के सभी सूचकांकों सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, ध्वस्त विधि व्यवस्था, आय-निवेश, खर्च-खपत, नौकरी-रोजगार, गरीबी-पलायन, एक समान प्रगति-एकरूप संवृद्धि तथा मानव विकास के तमाम संकेतकों में बिहार राष्ट्रीय औसत

से अत्यधिक कम और बहुत पीछे है। आशा है कि नए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बिहार की उन्नति, सुख-समृद्धि, शांति, सौहार्द, सुरक्षा और सर्वांगीण सुधार के लिए संकल्पित होकर सशक्त तरीके से काम करेंगे तथा बाहरियों के दिशा निर्देशों के आगे बिहारियों के स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखेंगे। प्रादुर्भाव से समाजवादी श्री सम्राट चौधरी जी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

पुलिस की बेलगामी पर अंकुश लगे

अदालतें न हो पुलिस की बेलगामी पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाता है। पुलिस कस्टडी में मौत के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच देश के न्यायालयों ने एक बार फिर पुलिस का वीभत्स चेहरा उजागर कर दिया है। आम लोगों की सुरक्षा के गठित किया गया पुलिस तंत्र किस कदर तानाशाह बन गया है, अदालतों के फैसलों ने इसे बेनकाब किया है। मद्रुरे की एक अदालत ने सातानुकुलम पुलिस स्टेशन में बाप-बेटे की मौत के मामले में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। तूतीकोरिन जिले के सातानुकुलम के व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 19 जून 2020 को कोरोना काल के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया और बुरी तरह पीटा। इसके बाद 21 जून को दोनों को कोविलपट्टी जेल में रखा गया। 22 जून की रात करीब 9 बजे बेनिक्स की मौत हो गई, जबकि अगली सुबह जयराज की भी मौत हो गई। इस मामले ने पूरे देश में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट की मद्रुरे बेंच ने खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी।

बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। इसी तरह लुधियाना जिले में करीब छह साल पहले रिकवरी एजेंट दीपक शुक्ला की थाना डिविजन नंबर 5 की पुलिस हिरासत में हुई थी। मौत के मामले में लुधियाना की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के तहत आरोप तय करने के आदेश जारी किए हैं। यह पूरा मामला फरवरी 2020 का है, जब पुलिस ने दीपक शुक्ला को वाहन चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया था। दीपक पर चोरी का झूठा मामला दर्ज कर उसे अमानवीय यातनाएं दीं। 26 फरवरी 2020 की रात दीपक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिसिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। दीपक के परिवार ने इंसाफ के लिए एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई लड़ी। पंजाब के मोगा जिले में भिंदर सिंह की मौत गैरकानूनी हिरासत में रखकर यातनाएं देने से हुई थी। न्यायिक जांच में सामने आया कि भिंदर सिंह को कथित तौर पर गैरकानूनी हिरासत में रखकर यातनाएं दी गईं। इस मामले में स्थानीय अदालत ने पंजाब पुलिस के पांच कर्मियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में ट्रायल चलाने का आदेश देते हुए केस को सेशन कोर्ट में भेज दिया है।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

इस्लामाबाद वार्ता में प्रवाह के सिद्धांत की अनदेखी

लेफ्टिनेंट ज. एसएस मेहता सेवानिवृत्त

आधुनिक दुनिया बात तो करती है शांति की, लेकिन व्यवहार करती है व्यवधान की मशीनरी के जरिए। युद्ध अब केवल सीमाओं या खंडकों तक सीमित नहीं; आपूर्ति शृंखलाएं बाधित होती हैं, वित्तीय प्रणालियां थरथराती हैं और डिजिटल नेटवर्क एवं समुद्री मार्ग रुकते हैं। प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र हमारे अस्तित्व के हर पहलू तक फैल चुका है, लेकिन शासकीय सिद्धांत अभी भी 17वीं सदी के 'वेस्टफेलियन संप्रभुता' के तर्क में अटकते हैं। हम बाड़ लगाने के औजारों से बाढ़ नियंत्रण में लगे हैं। मूल अंतर्दृष्टि : निरंतरता के रूप में स्थिरता- इतिहास एक शांत सत्य उजागर करता है, स्थिरता निरंतर आदान-प्रदान होते रहने से बनती है, न कि प्रतिद्वंद्विता के अभाव से। मार्ग मुक्त रहें और आवाजाही सुरक्षित रहे, तो दुनिया समृद्ध होती है। जब ये प्रवाह थम जाए, तो पतन होता है। स्थिरता प्रवाह संग चलती है।

यह हमारा गंतव्य न होकर वह गति है जिसे बनाए रखना होता है- जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शिनाख्त की थी, न कि आविष्कार। हमारे समय के व्यवधान एक अंतर्निहित नियम निरंतरता के पीछे-पीछे आती है। यह तर्क कोई नया नहीं। भौतिकी इसे काफी पहले कायम कर चुकी है। प्रवाह को प्रतिरोध द्वारा संरक्षित किया व बनाया जाता है, और अंतर से प्रवाह काम करता है। एकदम बांध दें, तो दबाव कहीं और बन जाएगा। तोड़ दें, तो तबाही मच जाएगी। ग्लोबल सिस्टम का व्यवहार भी इससे अलग नहीं। इस्लामाबाद वार्ता मिसाल कायम करने का मौका गंवाया- इस्लामाबाद में बहुत बड़े दांवों वाली वार्ता में, मिसाल कायम करने का अवसर गंवा डाला। सप्ताहों तक बढ़ती गई तनातनी के बाद दोनों पक्ष मिले। अपनी-अपनी स्थिति का बचाव करते रहे, इतिहास का हवाला दिया, और रेड लाइंस खिंची। लेकिन वे खाली

हाथ लौटे। जो कुछ हुआ, वह कोई वार्ता नहीं रही; यहां एक मिसाल कायम करने का मौका गंवा दिया। दोनों पक्षों को आगे बढ़ने के लिए जिस चीज की सर्वाधिक जरूरत थी, उनमें से कुछ भी सामने नहीं रखा। वार्ताकार आगे की राह टटोलने की बजाय अपनी-अपनी स्थितियां न्यायोचित ठहराने तक सीमित रहे। वे विरोधी के रूप में मिले। चाहते तो 'प्रवाह के संरक्षक' के रूप में लौट सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया। जब गौरव या जमीन के मुद्दे पर बातचीत हो, तो हम वहीं अटक जाते

प्रणालियों को पुनः अराजकता की ओर धकेल देता है। अगले दशकों में जीवित रहने के दायित्व का तालमेल निर्भरता से बैठाना होगा। जरूरी प्रवाह रुके नहीं। खुले मार्गों से साझा नियमों तक : समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि गहरे समुद्र जैसे कुछ क्षेत्र खुले रहने चाहिए। इस प्रावधान ने पहुंच संरक्षित रखी; लेकिन निरंतरता सुनिश्चित नहीं की। प्रवाह का नियम इसमें अनिवार्य सुधार होना चाहिए। तब यह पहुंच को दायित्व में बदल देगा, परस्पर जुड़ी दुनिया में, मार्ग न केवल खुले, बल्कि कार्यात्मक भी रहें। अहम



हैं। जब अस्तित्व की साझा जीवन-रेखाओं पर बात करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। क्षैतिज गुरुत्वाकर्षण : नया स्थिरांक-अब हम किसी के सिंहासन के आकार या सीमा बहुत दूर होने से अधिक प्रभावित नहीं। नया स्थिरांक है आपसी निर्भरता; अदृश्य खिंचाव, जो ऊर्जा मार्ग, डेटा नेटवर्क और वित्तीय प्रणालियों को एकीकृत कार्यशील हकीकत में बांधता है। लंबवत ऊंचाई के लिए जैसे गुरुत्वाकर्षण काम करता है, वही काम क्षैतिज दिशा में प्रवाह का है। यह आम सहमति का इंतजार नहीं करता, न ही किसी आचार-संहिता से चालित है; यह तो बाध्यकारी है। पारस्परिक निर्भरता को हम नहीं चुनते; बल्कि इसी संग जन्म लेते हैं। आधुनिक राष्ट्र के लिए प्रवाह को नकारना ऑक्सीजन को नकारने जैसा है। प्रकृति का प्रथम नियम- प्रवाह प्रकृति का प्रथम नियम है निरंतरता से ही स्थिरता बनी रहती है; इसमें आया व्यवधान

मार्गों का प्रवाह रोकने से फायदा नहीं होता; यह तो प्रणालीगत जोखिम है। यदि यह सिद्धांत इस्लामाबाद में हुई चर्चा में रखा होता, तो वार्ता अपनी-अपनी स्थिति का बचाव करने से हटकर मार्गों पर स्थिति की ओर मुड़ जाती व मिसाल कायम होती- समझौते के लिए नहीं, निरंतरता के लिए।

साझापन में विस्तार : साझापन की जरूरतें बदल चुकी हैं। वे अब केवल महासागर व वायुमंडल तक सीमित नहीं; उनमें अब ऊर्जा गलियारा, व्यापारिक जलमार्ग और इंटरनेट की फाइबर-ऑप्टिक शामिल हैं। ये संपत्तियां न होकर जीवित रखने योग्य जीवन-रेखाएं हैं। इन पर किसी का एकाधिकार नहीं हो; इनकी देखभाल हो। इनमें पड़े व्यवधान का असर वैश्विक स्तर पर होता है क्योंकि परस्पर निर्भरता एक योजना है, विकल्प नहीं। आवश्यकता संप्रभुता के समर्पण की नहीं बल्कि निरंतरता की रक्षा करने वाले मानदंडों का विस्तार करने की है।

मुकुल व्यास

दुनिया के जंगल हमारे पारिस्थितिक तंत्र का आधार हैं और ग्लोबल वार्मिंग से लड़कर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब उनकी विशिष्ट भूमिका कमजोर हो रही है क्योंकि जंगलों में तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों की भरमार हो रही है और लंबे समय तक जीने वाली प्रजातियां तेजी से गायब हो रही हैं। स्थिर और लंबे जीवनकाल वाले पेड़ों की जगह तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों को रखना टिम्बर इंडस्ट्री और जंगल की आग के बाद जल्दी संभलने के लिए फायदेमंद है लेकिन बदलते मौसम का सामना करते समय यह जंगलों को बहुत ज्यादा खतरे में डालता है। डेनमार्क की ओरहुस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 31,001 पेड़ों की प्रजातियों का वैश्विक विश्लेषण करके बताया है कि तेजी से बढ़ने वाले पेड़ किन जंगलों में हावी हो रहे हैं।

डेनिश वैज्ञानिक जेन्स-क्रिश्चियन स्वेनिंग ने नकशों का इस्तेमाल करके दिखाया कि धीरे-धीरे बढ़ने वाले, खास किस्म के पेड़ तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों के आगे हार रहे हैं। स्वेनिंग ने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में ऐसे कई छोटे पेड़ों का उल्लेख किया है जिनके गायब होने की संभावना सबसे ज्यादा है। एक बार जब तेजी से बढ़ने वाले पेड़ किसी जगह पर हावी हो जाते हैं, तो तूफान, सूखा और कीड़े उस जंगल के बड़े हिस्से को एक साथ गिरा सकते हैं। दरअसल, लकड़ी काटने, सड़क बनाने और आग लगने से खुली धूप वाली जगहें बन जाती हैं, जहां तेजी से बढ़ने वाले पेड़ बहुत जल्दी फैल जाते हैं। हल्की पत्तियों और मुलायम लकड़ी की वजह से ये पेड़ तेजी से बढ़ते

जंगलों की कम होती ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की क्षमता



हैं। सूखे या गर्मी की वजह से पानी की कमी होने पर भी ऐसे पेड़ों का बढ़ना जारी रहता है। इन पेड़ों में लकड़ी का घनत्व कम होता है, जिसकी वजह से इनके तने आसानी से टूट जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। विषम परिस्थितियों में हल्की लकड़ी वाले पेड़ों के मरने की संभावना अधिक होती है। लंबे समय तक चलने वाले पेड़ धीरे-धीरे बढ़ते थे।

मौसम खराब होने पर उनकी गहरी जड़ें और मजबूत तने जंगल को एक साथ बनाए रखते थे। घनी लकड़ी और मजबूत पत्तियों ने उन्हें सूखे और कीड़ों से बचने में मदद की। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने ऐसे पेड़ों के टिकाऊपन को जलवायु सुरक्षा से जोड़ा है। इस तरह के पेड़ जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं और स्थिरता और कार्बन भंडारण में योगदान देते हैं। जैसे-जैसे तूफान, कटाई और गर्मी से जंगलों पर दबाव बढ़ता है, पेड़ों की बाहरी प्रजातियां रोशनी, पानी और पोषक तत्वों के लिए मूल पौधों को घेर लेती हैं। यह दबाव दुर्लभ स्थानीय पेड़ों को खत्म होने के करीब ला सकता है। उष्णकटिबंधीय जंगलों में कई

पेड़ों की प्रजातियां छोटे-छोटे इलाकों में मिलती हैं, इसलिए कुछ पेड़ों के खत्म होने से पूरा खाद्य चक्र तेजी से कम हो सकता है। जंगल कार्बन सिंक का काम करते हैं, वे जितना कार्बन छोड़ते हैं उससे कहीं ज्यादा मात्रा में उसे हटाते हैं। धीरे-धीरे बढ़ने वाले घने पेड़ों ने दशकों तक तनों में कार्बन को बंद रखा, क्योंकि ठोस लकड़ी के हर इंच में ज्यादा पदार्थ समा सकता है। तेजी से बढ़ने वाले पेड़ अक्सर कम उम्र में मर जाते हैं। उनके तने हल्के होते हैं, इसलिए उनमें जमा कार्बन तूफान और क्षय से जल्दी हवा में वापस चला जाता है। इससे जंगल लंबे समय तक कार्बन जमा करने में कम असरदार हो जाते हैं।

सही पेड़ों के बिना जंगल उन पक्षियों और स्तनपायी जीवों को खो सकते हैं जो बीज फैलाते हैं, जिससे तूफान या आग के बाद जंगल में रिकवरी धीमी हो जाती है। जंगल के प्रबंधक अक्सर जल्दी फसल के लिए तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों को पसंद करते हैं, लेकिन जब पौधों में धीमी गति से बढ़ने वाली प्रजातियां भी शामिल होती हैं, तो जंगल लंबे समय तक अपनी

मजबूती बनाए रख सकते हैं। ज्यादा पेड़ चुनने से दुर्लभ आनुवांशिकी सुरक्षित रहती है और जब मौसम का तनाव बढ़ता है, यह जंगल में पुराने विकास वाले गुणों को बनाए रखती है। एक अन्य अध्ययन में वैज्ञानिकों ने जंगलों की एक और भूमिका को उजागर किया है। अध्ययन में पाया गया कि वन की मिट्टी जलवायु परिवर्तन में जितना योगदान दे रही है, उसका हमें अंदाजा नहीं है। यह साल दर साल चुपचाप हवा से मीथेन को अवशोषित करती रहती है।

दक्षिण-पश्चिम जर्मनी में लिए गए नए दीर्घकालिक मापों से पता चलता है कि कुछ वनों में यह भूमिगत मीथेन अवशोषण क्षमता कम होने के बजाय लगातार मजबूत होती जा रही है। जर्मनी के गोटींगेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लगभग 25 वर्षों तक 13 वन भूखंडों में मीथेन के मूवमेंट का अध्ययन किया और पाया कि मिट्टी की मीथेन अवशोषण क्षमता में प्रति वर्ष लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह निरंतर वृद्धि नम और शुष्क दोनों मौसमों और धीरे-धीरे बढ़ते तापमान के दौरान देखी गई। यह वृद्धि इस धारणा को चुनौती देती है कि जलवायु परिवर्तन से मिट्टी की मीथेन अवशोषण क्षमता में एक समान कमी आएगी। नया अध्ययन इस बारे में भी नए सवाल खड़े करता है कि कुछ वन दूसरों की तुलना में तेजी से क्यों बेहतर हो रहे हैं। वनों के सूक्ष्मजीव मीथेन को अवशोषित करते हैं। कम वर्षा के कारण मिट्टी में वायु के लिए अधिक स्थान बचता है, जिससे मीथेन सतह के पास रहने के बजाय तेजी से नीचे की ओर जा सकती है। शुष्क मिट्टी में हवा से भरे छिद्र अधिक होते हैं जिससे मीथेन और ऑक्सीजन दोनों मिट्टी में आसानी से प्रवाहित हो जाते

ओट्स मिक्स

अगर आपके पास इंस्टेंट ओट्स हैं, तो उन्हें दही या दूध के साथ मिलाकर भी खाया जा सकता है। इसमें आप फल या ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं।



फ्रूट चाट

फ्रूट चाट एक हेल्दी और टेस्टी स्नैक है। इसके लिए आप सेब, केला, पपीता और अनार काटकर उसमें चाट मसाला और नींबू डाल सकते हैं। बाजार में मिलने वाली पैकड फ्रूट चाट में चाट मसाला मिलाया जाता है, जिससे फलों के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। अगर आपको फ्रूट चाट खानी है तो इस पर किसी भी तरह का नमक या चाट मसाला न मिलाएं।

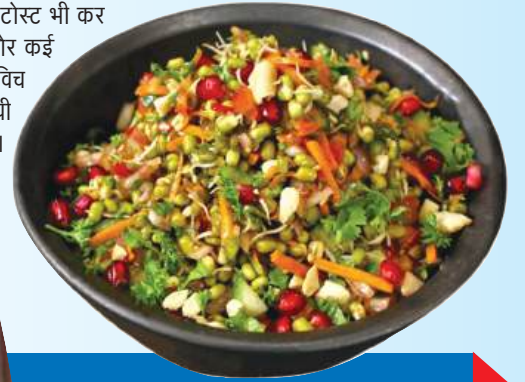
फ्रूट कर्ड

यह भी बिना गैस सिलेंडर के आसानी से बनाया जा सकता है और हेल्दी स्नैक्स भी है। फ्रूट कर्ड बनाने के लिए सेब, केला, पपीता, अंगूर या अपनी पसंद के फलों में दही, चीनी, और चाट मसाला मिलाकर स्वादिष्ट स्नैक बना सकते हैं।



वेज सैंडविच

वेज सैंडविच सबसे आसान और जल्दी बनने वाली डिश है। इसे बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस में कटे हुए खीरा, टमाटर और प्याज रखें। नमक, चाट मसाला और सॉस डालें। कुछ ही मिनटों में टेस्टी सैंडविच तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तब तो आप ब्रेड को टोस्ट भी कर सकते हैं। और कई तरह के सैंडविच या अन्य रेसिपी बना सकते हैं।



स्पाउट सलाद

स्पाउट सलाद सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए अंकुरित मूंग, टमाटर, प्याज, नींबू और नमक चाहिए। इन सब को मिलाकर हेल्दी सलाद तैयार किया जा सकता है। ये देर तक पेट भरा रखता है।

पीनट बटर टोस्ट

पीनट बटर टोस्ट भी एक आसान और एनर्जी से भरपूर स्नैक है। बस ब्रेड पर पीनट बटर लगाएं और चाहे तो ऊपर केले के स्लाइस भी डाल सकते हैं।

बिना गैस के भी बन सकता है टेस्टी खाना

कभी कबार घर में किसी कारणवश गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है जिससे हम खाना बना सकें। लेकिन अगर आपके घर गैस उपलब्ध नहीं है तो भी आप कुछ ऐसे डिश हैं जिन्हें बिना गैस के भी तैयार किया जा सकता है। जिन्हें बनाने के लिए गैस या ज्यादा कुकिंग की जरूरत नहीं होती है। ये डिश न सिर्फ जल्दी बन जाती हैं बल्कि स्वादिष्ट भी होती हैं। ये आसान डिश न सिर्फ समय बचाएंगी, बल्कि इमरजेंसी में बेहद काम की साबित हो सकती हैं। इसलिए घर में हमेशा कुछ नो-कुक फूड आइटम जैसे मुरमुरे, ब्रेड, फल और अंकुरित दालें रखें। ताकि गैस न होने पर भी आसानी से खाना बनाया जा सकता है।



भेलपुरी

भेलपुरी एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए मुरमुरे, बारीक कटा प्याज और टमाटर, हरी चटनी और इमली की चटनी मिलाकर स्वादिष्ट भेलपुरी तैयार करें।

हंसना मना है

बाप-बेटा अगर ससुराल वाले स्कूटर दे तो कार मांगना, कूलर दे तो एसी मांगना, लड़का - पापा अगर वो लड़की दे तो उसकी मां को भी मांग लूं क्या?

टीचर ने गधे के सामने 1 दारु की और 1 पानी की बाल्टी रखी, गधा पानी पी गया। टीचर- तुमने इस से क्या सिखा? स्टूडेंट- जो दारु नहीं पिता वह गधा होता है!

एक आदमी मेडिकल शॉप पर जहर लेने गया। आदमी- एक जहर की बोतल देना, दुकानदार- बिना पर्ची के जहर नहीं मिल सकता। आदमी ने शादी का कार्ड दिखाया.. दुकानदार- बस कर पगले, रुलाएगा क्या? बड़ी बोतल दूं या छोटी?

एक फैमिली शोले फिल्म देख कर अपने घर आयी। तभी पति ने पत्नी से, रोमांटिक अंदाज में कहा, नाच बसंती नाच.. तभी उनका छोटा बच्चा बोला, नहीं मम्मी ईस कुत्ते के सामने मत नाचना!

भिखारी- साहब एक रुपया दे दो। साहब- तुम्हें शरम नहीं आती, रोड पर खड़े होकर भीख मांगते हो, भिखारी- अब तुझसे एक रुपये मांगने के लिए ऑफिस खोलूं क्या?

दो शेर जंगल में बैठे थे, पास से एक खरगोश गुजरा, आहट सुनकर एक शेर ने दूसरे से पूछा- क्या है? कुछ नहीं, फास्ट फूड है!

कहानी | बगुला भगत और केकड़ा

एक जंगल में आलसी बगुला रहता था। उसे खाना ढूँढने में भी आलस आता था। जिस कारण उसे कई दिन भूखा रहना पड़ता था। एक बार उसे एक आइडिया सूझा। वह उस योजना को सफल बनाने में जुट गया। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे-मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे रोता देख केकड़ा उसके पास आया और पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है? रो क्यों रहे हो? बगुला रोते-रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। बगुला बोला, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है, भाई। वैसे भी मुझे कल त्रिकालीन बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। अच्छा, कछुए ने चौक कर पूछा, तो फिर इसका क्या हल है? बगुले भगत ने कहा, यहां से कुछ कोस दूर एक तालाब है। हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहां का पानी कभी नहीं सूखता। मैं सभी वहां छोड़कर आ सकता हूँ। यह सुनकर जानवर खुश हो गए। अगले दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक-एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। उस चट्टान पर जीवों की हड्डियां का ढेर लगने लगा था। बगुला ने सोचा दुनिया भी कैसे मूर्ख है। इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया, तूम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो। मेरा नंबर कब आएगा? तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूँ। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुंचे, तो केकड़े ने वहां हड्डियां देखी उसने तुरंत बगुले से पूछा कि ये हड्डियां किसकी हैं और जलाशय कितना दूर है? बगुला जोर जोर से हंसते हुए बोला, कोई जलाशय नहीं है और ये सारी तुम्हारे साथियों की हड्डियां हैं, जिन्हें मैं खा गया। उसकी यह बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन अपने पंजों से पकड़ ली। कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। इसके बाद, केकड़ा लौट कर नदी के पास गया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी जय जयकार की।

7 अंतर खोजें



जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951



पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

मेघ 	नौकरी में कार्यभार रहेगा। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। आय में निश्चितता रहेगी। जोखिम न लें। एकाएक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लापरवाही न करें।	तुला 	सुख के साधन जुटेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यवसाय लाभदायक रहेगा।
वृषभ 	व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा। लाभ देगा। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। प्रतिबद्धता में वृद्धि होगी। प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।	वृश्चिक 	तंत्र-मंत्र में रुचि जागृत होगी। किसी जानकार व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।
मिथुन 	दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नए काम करने का मन बनेगा। फिजूलखर्ची ज्यादा होगी। शत्रु भय रहेगा। शारीरिक कष्ट से बाधा उत्पन्न होगी।	धनु 	भागदौड़ होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। लाभ के लिए प्रयास करें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। पार्टनरों से कहसानी हो सकती है।
कर्क 	व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में अधिकार बढ़ने के योग हैं। कोई बड़ी समस्या का अंत हो सकता है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें।	मकर 	व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि अपमान हो। व्यापार-व्यवसाय अनुकूल रहेगा।
सिंह 	स्वयं के काम पर ध्यान दें। बनते काम बिगड़ सकते हैं। विवाद को बढ़ावा न दें। चिंता तथा तनाव रहेंगे। व्यापार ठीक चलेगा। कार्यकुशलता कम होगी।	कुम्भ 	भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहेगी। आशंका व कुशंका रहेगी।
कन्या 	व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। भाग्य का साथ मिलेगा।	मीन 	यात्रा मनोरंजक रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अज्ञात भय रहेगा।

देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश कर रही भाजपा : राहुल

» पीएम को जादूगर बताने पर भड़की बीजेपी, माफी मांगने की रस्खी मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जादूगर कहकर सदन में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। महिला आरक्षण विधेयक पर बहस को संबोधित करते हुए गांधी ने भाजपा पर देश का चुनावी नक्शा बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की राजनीति में जो हो रहा है उससे डरे हुए हैं, अपनी ताकत के कम होने से डरे हुए हैं, और इसलिए भारत का राजनीतिक नक्शा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने असम और जम्मू-कश्मीर में ऐसा किया, और अब सोच रहे हैं कि आप पूरे भारत में ऐसा कर सकते हैं।

इसके लिए आपको संविधान में संशोधन की जरूरत है। गांधी ने कहा कि भाजपा जानती थी कि विधेयक सदन में पारित नहीं होगा और इसलिए घबरा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सच तो यह है कि



मेरे और पीएम के बीच पत्नी वाला मसला नहीं

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने शुक्रवार को संसद के चल रहे विशेष सत्र के दौरान चल रही तीखी बहस के बीच हल्के-फुल्के अंदाज में बात की। यह सत्र तीन विधेयकों पर विचार-विमर्श और मतदान के लिए बुलाया गया है, जिनका उद्देश्य 29 में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करना सुनिश्चित करना है। लोकसभा में बोलते हुए, कांग्रेस सांसद ने स्वीकार किया कि लगभग हर किसी के जीवन में एक महिला का महत्वपूर्ण प्रभाव रह है, चाहे वह मां, बहन या पत्नी के रूप में हो।

जादूगर पकड़ा गया है। बालाकोट का जादूगर, नोटबंदी का जादूगर, सिंदूर का जादूगर अचानक पकड़ा गया है। उन्होंने आगे कहा कि सब जानते हैं कि हमारे दोस्त, जादूगर और व्यवसायी के बीच साझेदारी है। राहुल गांधी की टिप्पणियों पर भाजपा

सांसदों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि गांधी प्रधानमंत्री के लिए गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और बालाकोट हमलों और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर देश और सेना को बदनाम कर रहे हैं।

राजनाथ ने मोर्चा संभाला



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से राहुल गांधी की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस्तेमाल किए गए शब्द बेहद दुर्भावपूर्ण हैं। मेरा मानना है कि इसकी निंदा करना काफी नहीं है। सिंह ने कहा कि उन्हें बार-बार 'जादूगर' कहना वास्तव में देश की जनता का अपमान है। इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए।

हम सभी अपने जीवन में महिलाओं से बहुत प्रभावित हुए हैं: नेता प्रतिपक्ष

राहुल ने कहा कि महिलाएं एक केंद्रीय शक्ति होती हैं, जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की कल्पना और हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक प्रेरक शक्ति हैं। हम सभी अपने जीवन में महिलाओं, माताओं, बहनों और प्रकृतियों से बहुत प्रभावित हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि रीजिजू ने कहा है, लेकिन न तो मेरे पास और न ही प्रधानमंत्री के पास पत्नी वाला मसला है, इसलिए हों उन नजदिक से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। लेकिन हमारी मां और बहन हैं।

भाजपा उम्मीदवारों के पर्चे बांट रहे सीआरपीएफ जवान : डेरक ओब्रयन

» बंगाल में वोटिंग से पहले टीएमसी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को लिखी चिट्ठी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरक ओ'ब्रयन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा जारी फोर्स डिप्लॉयमेंट इन इलेक्शंस मैनुअल, 23, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय न्याय संहिता, 23 का उल्लंघन किया गया है। पत्र में फेसबुक पर प्रसारित एक वीडियो के आधार पर यह शिकायत की गई है।



इस वीडियो में कुछ नागरिक यह दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवान कथित तौर पर भाजपा उम्मीदवारों के साथ घूम रहे थे, भाजपा के पर्चे बांट रहे थे और मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे थे। पत्र में कहा गया है कि यह व्यवहार कथित तौर पर आपराधिक धमकी और चुनावी प्रक्रिया में अनुचित प्रभाव (धारा 174) के तहत अपराध है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि इस तरह की गतिविधियां मतदाताओं में डर का माहौल पैदा करती हैं और स्वतंत्र मतदान के अधिकार को प्रभावित करती हैं। टीएमसी ने यह भी कहा है कि सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय बलों का चुनाव ड्यूटी के दौरान निष्पक्ष रहना अनिवार्य है और इस तरह का व्यवहार चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। पत्र में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 और 129 का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी पुलिस बल के सदस्य को मतदाताओं को प्रभावित करने या किसी भी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अनुमति नहीं है। टीएमसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि संबंधित सीआरपीएफ कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं, सभी केंद्रीय बलों को बंगाल में निष्पक्षता और आयोग के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जाएं।

जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी चेन्नई

» सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला आज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

हैदराबाद। आईपीएल के 19वें सीजन के सप्ताहसर्वे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भिड़ंत होने जा रही है। ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खराब शुरुआत के बाद जीत की पट्टी पर लौट आई है। संजू सैमसन के फार्म के लौटते ही चेन्नई दो मैच में जीत दर्ज कर चुकी है। हालांकि अबतक सीजन में खेले पांच मैच में दो जीत और तीन हार के साथ आठवें पायदान पर है। वहीं दूसरी तरफ मेजबान हैदराबाद की टीम 5 मैच में 2 जीत और तीन हार के साथ अंक

सत्र की पहली जीत को तरसी केकेआर, गुजरात से भी हारी मैच

अहमदाबाद। गुजरात टाइटंस ने केकेआर को पांच विकेट से हरा दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने कैमरून ग्रीन की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 10 विकेट पर 180 रन बनाए। जबकि गुजरात ने 19.4 ओवर में पांच विकेट पर 181 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह केकेआर की इस सीजन में पांचवीं हार है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। फिर 32 के स्कोर पर तीन विकेट गंवाकर मुश्किल में दिख रही केकेआर की पारी को रोचमैन पॉवेल और कैमरून ग्रीन ने संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 55 रन जोड़े। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात के लिए साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर 57 रन जोड़े। इसके बाद जोस बटलर और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 38 रन जोड़े। हालांकि, कप्तान शुभमन गिल ने एक छोर से अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपना अर्धशतक पूरा किया।

अबतक अपनी लय हासिल नहीं कर सकी है। अपने आखिरी मुकाबले में हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स का विजय रथ रोका था। एक बार फिर वो यही कारनामा सीएसके के खिलाफ करना चाहेगी। (सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल के इतिहास में अबतक कुल 22 मैच खेले गए हैं। इनमें से हैदराबाद को 7 और सीएसके को 15 मैच में जीत हासिल हुई है। दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले पांच मैच में से तीन मैच में सीएसके को जीत मिली है और दो मैच हैदराबाद के नाम रहे हैं। हैदराबाद के मैदान पर दोनों के बीच पांच ही मैच खेले गए हैं जिसमें से हैदराबाद को तीन और चेन्नई को दो मैच में जीत मिली। ऐसे में इस मैदान पर हैदराबाद और चेन्नई के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।

राहुल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि कांग्रेस नेता के पास दोहरी नागरिकता होने के आरोपों की जांच आवश्यक है। न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह या तो स्वयं जांच करे या मामले को जांच के लिए किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दे। यह टिप्पणी भाजपा कार्यकर्ता एस. विमेश शिशिर द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें उन्होंने लखनऊ की विशेष सांसद/विधायक अदालत द्वारा 28 जनवरी को पारित आदेश को चुनौती दी थी।

निचली अदालत ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले, उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एक विशेष अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जारी एक मानहानि मामले की शुरुआत के सुनवाई के दौरान वादी पक्ष

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोहरी नागरिकता के आरोपों के मामले में दिया फैसला

के रवैये पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने की हिदायत दी। राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत एक प्रार्थना पत्र पर बहस होनी थी लेकिन वादी पक्ष के वकील ने एक बार फिर स्थगन की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। वादी पक्ष पिछले कई तारीखों से लगातार स्थगन की मांग कर रहा है, जिससे मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है और इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर अगली तिथि पर वादी पक्ष बहस के लिए उपस्थित नहीं होता तो उनके विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

प्रमाण पत्र के नाम पर खुली लूट!

» 25 रुपये के काम के लिए 25 हजार तक वसूली
» जिम्मेदार अधिकारी से लेकर नगर आयुक्त तक खामोश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम जोन-1 में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर खुलेआम लूट का खेल चल रहा है। आरोप है कि जिस काम की सरकारी फीस महज 25 रुपये के बीच निर्धारित है, उसी काम के लिए आम जनता से हजारों रुपये वसूले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर नगर आयुक्त तक की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है, जिससे बाबू और बाहरी लोगों की मिलीभगत जनता को लूटा जा रहा है।



सूत्रों के अनुसार, जोन-1 में पुराने जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र को कैंसिल कराने के लिए लोगों से 15 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की मांग की जा रही है। वहीं नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी लोगों को तहसील का हवाला देकर 2 हजार से 3 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। वेरिफिकेशन के नाम पर भी मनमानी रकम तय कर दी जाती

बाबू और लोगों की मिलीभगत से हो रही अवैध वसूली

बाबू और प्राइवेट लोगों की मिलीभगत से सर्टिफिकेट बनवाने से लेकर वेरिफिकेशन तक हर स्तर पर अवैध वसूली की जा रही है। नगर निगम जैसे सरकारी कार्यालय में जहां जनता अपने जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए आती है, वहीं उन्हें मजबूरी में बिचौलियों के चक्कर लगाते पड़ रहे हैं। कई लोगों का आरोप है कि बिना पैसे दिए उनका काम महीनों तक लटका दिया जाता है, जिससे परेशान होकर उन्हें मोटी रकम देनी पड़ती है। नगर आयुक्त को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी कर्मचारियों व बिचौलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

है और बिना पैसे दिए फाइल आगे नहीं बढ़ती। बताया जा रहा है कि इस पूरे खेल में कुछ जिम्मेदार बाबूओं के साथ-साथ बाहरी और प्राइवेट लोग भी सक्रिय हैं। नगर निगम कार्यालय में ऐसे बिचौलियां खुलेआम घूमते नजर आते हैं जो खुद को काम कराने वाला बताकर जनता से मोटी रकम वसूल लेते हैं।



महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के गिरते ही एनडीए व मोदी सरकार पर चौतरफा प्रहार

- » विपक्ष बोला- पीएम मोदी का पतन जल्द ही होने वाला है
- » राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र को बचाया
- » कांग्रेस, सपा, शिवसेना यूबीटी ने भाजपा पर साधा निशाना

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। देश की संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक दो तिहाई बहुमत न होने की वजह से पास नहीं हो पाया। इस बीच राहुल गांधी को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष ने एडीए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी से लेकर सपा तक ने मोदी सरकार पर चौतरफार वार शुरू कर दिया है।

राहुल गांधी के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कल देश के लोकतंत्र बचाने के आंदोलन का नेतृत्व किया है। राहुल गांधी देश के बहुत प्रभावशाली नेता हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने कल एक बहुत बड़ी जंग को जीत में बदल दिया है।



यह एक राजनीतिक साजिश थी : संजय राउत

सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महिला आरक्षण विधेयक एक राजनीतिक साजिश थी, और यह विफल हो गई। यह मोदी और उनके गुट के पतन की शुरुआत है। वे महिला आरक्षण की आड़ में मनमाने ढंग से मतदाताओं के गठबंधन में हेरफेर करके सभी चुनाव जीतना चाहते थे। संसद में उनकी ये योजनाएं धरशाही हो गईं, वे लोकसभा सीटों की संख्या मनमाने ढंग से नहीं बढ़ा सके, लेकिन उन्हें संविधान की शक्ति और अपनी वास्तविक ताकत का एहसास हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री का पद केवल 16 सांसदों के बहुमत पर टिका है, अगर ये 16 भी कम हो गए, तो उन्हें अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर बाहर जाना पड़ेगा। आज के घटनाक्रम का यही अर्थ है। मोदी का पतन जल्द ही होने वाला है, मेरी बात याद रखना राहुल गांधी ने उन 16 सांसदों के गले में फंदा डाल दिया है। संजय राउत ने बिल पेश होने से पहले कहा था कि महिला आरक्षण के आड़ में जो परिसीमन का खेल चल रहा है, वह बहुत गंभीर है, बीजेपी अपने अनुभार पॉलिटिकल गैप बनाने की कोशिश कर रही है।



परिसीमन की वजह से किया संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का विरोध : खरगे

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक के सांसद महिला विरोधी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ एनडीए सरकार सत्ता हासिल करना चाहती है ताकि सदन में साधारण बहुमत से किसी भी परिसीमन कानून को पारित या संशोधित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें परिसीमन का प्रावधान है। संसद परिसर से एनआई को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि हम महिला विरोधी नहीं हैं और हम लंबे समय से एक तिहाई महिला आरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हमने सर्वसम्मति

से 023 के संशोधन का समर्थन किया और उसे पारित कराया। हालांकि, इसकी आड़ में उन्होंने एक और संशोधन पेश किया, जिसमें परिसीमन का प्रावधान जोड़कर महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को समेकित कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा संविधान की संरचना को बदलना चाहती है और कार्यपालिका शक्ति को अपने हाथों में लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि इन तीनों विधेयकों को एक साथ लाकर वे सत्ता हासिल करना चाहते हैं ताकि किसी भी परिसीमन कानून को साधारण बहुमत से सदन में पारित और संशोधित किया जा सके... आपको यह 543 सदस्यों के भीतर करना चाहिए। अगली जनगणना या जाति जनगणना पूरी होने के बाद, आप इसे अगले चुनाव में पूरा कर सकते हैं... आपको इरादा संविधान की संरचना को बदलना और कार्यपालिका शक्ति को अपने हाथों में लेना है।

लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही थी सरकार : प्रियंका गांधी

लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पारित न होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ, वह लोकतंत्र और संविधान की बड़ी जीत है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार संघीय ढांचे को कमजोर करने और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही थी, जिसे विपक्ष ने मिलकर विफल कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसी भी तरह सत्ता में बने रहने की रणनीति बना रही है और इसके लिए महिलाओं के मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक, सरकार की सोच थी कि अगर बिल पास हो जाता तो उसे राजनीतिक फायदा मिलता, और अगर नहीं होता तो वह अन्य दलों को महिला विरोधी बताकर खुद को महिलाओं का मसीहा दिखाने की

कोशिश करती। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं का मसीहा बनना आसान नहीं है और सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे एक राजनीतिक रणनीति कहा। केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के हालिया फैसलों में अंतरराष्ट्रीय दबाव साफ दिखता है। अमेरिका के साथ हुए समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी शर्तें सामान्य परिस्थितियों में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करता। महंगाई को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि गैस, फल-सब्जियों और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा बोझ महिलाओं पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक, सरकार इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक गतिविधियों और प्रचार का सहारा ले रही है।



पीएम मोदी के प्रयासों को झटका : ललन सिंह

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने शनिवार को लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 26 के पारित न हो पाने के बाद विपक्ष की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल में बाधा डाली है और जोर देकर कहा कि महिला मतदाता इस घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देंगी।

जदयू नेता बोले कांग्रेस ने महत्वपूर्ण पहल में बाधा डाली

विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विधेयक की हार को लोकतंत्र की जीत करार देने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिंह ने कहा कि विपक्ष उस ऐतिहासिक पहल को झटका दे रहा है जिसे उन्होंने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल बताया। सिंह ने बताया कि विपक्ष का कहना है कि इस विधेयक का गिरना एक ऐतिहासिक कदम है। उनके अनुसार, यह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि उन्होंने देश में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों को विफल कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके देश की लगभग आधी आबादी वाली महिलाओं को न्याय दिलाना था। आधी आबादी महिलाएं हैं, और संसद में उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण देना उनके साथ न्याय करने की दिशा में उठाया गया कदम था। अब वे इसे गिराकर बड़ी संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि उसने तिहासिक रूप से प्रमुख सामाजिक सुधारों का विरोध किया है। सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस का चरित्र है। उन्होंने हमेशा समाज में सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक क्रांति के कदमों को रोकने की कोशिश की है।



नोएडा के बाद हापुड़ में भड़के श्रमिक, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर फूटा गुस्सा

4पीएम न्यूज नेटवर्क

पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र स्थित दो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का गुस्सा वेतन बढ़ाव की मांग को लेकर फूट पड़ा। कर्मचारियों ने एकजुट होकर अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कामकाज प्रभावित हो गया। स्थिति तेजी से बिगड़ने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित किया। कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन प्रबंधन की ओर से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी अनदेखी से नाराज होकर कर्मचारियों ने विरोध का रास्ता अपनाया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा वेतन में गुंजागरि करना मुश्किल हो रहा है और बार-बार मांग रखने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। विरोध के दौरान कर्मचारियों का कहना है कि जब तक वेतन बढ़ाव की मांग को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।

तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, केरल के 9 शिक्षकों की मौत

4पीएम न्यूज नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु के सेलम जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। सेलम-कोयंबटूर नेशनल हाईवे पर एक सरकारी बस के अनियंत्रित होकर सड़क से उतरने और कई वाहनों से टकराने के कारण कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। मारे गए सभी लोग पेशे से शिक्षक थे और केरल के मलप्पुरम जिले के रहने वाले थे। समाचार एजेंसी, हट्टू की रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे में जिन लोगों की जान गई, वे सभी पेशे से शिक्षक थे। जिला कलेक्टर के दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक, बस कोयंबटूर से सेलम की ओर जा रही थी। 13वें हैयरपिन मोड़ पर ड्राइवर का बस से कंट्रोल हट गया, जिसके बाद बस अचानक सड़क से उतर गई। बस एक दोपहिया वाहन और एक ऑटो-रिक्शा से टकरा गई, जिसमें करीब 10 यात्री सवार थे।

होर्मुज पर खत्म नहीं हो रही तनातनी!

» अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से वापस लौटे 21 जहाज, ईरान ने दी चेतावनी

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर की डेडलाइन जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनातनी फिर से बढ़ने लगी है। फिलहाल होर्मुज खुलने की घोषणा के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ने होर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे जहाजों के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि सभी तरह के आवागमन के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी से अनुमति लेना जरूरी है। नागरिक जहाजों को केवल ईरान द्वारा तय किए गए रास्ते से गुजरने की अनुमति है, जबकि सैन्य जहाजों के वहां से गुजरने पर अभी



भी रोक है। अगर इजाजत नहीं ली जाती है तो इसे फिर से बंद कर दिया जाएगा। आईआरजीसी नेवी ने इन शर्तों को एक नई व्यवस्था बताया और कहा कि यह सीजफायर समझौते की शर्तों अनुरूप है। हालांकि, इस बयान में उन विवरणों का जिक्र है जिनमें अराधची ने तब स्पष्ट नहीं किया था, जब उन्होंने यह घोषणा की थी कि संघर्ष-विराम के दौरान सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए मार्ग पूरी तरह से खुला है। उन्होंने कहा था, लेबनान में संघर्ष-विराम के अनुरूप होर्मुज स्ट्रेट से सभी वाणिज्यिक जहाजों के गुजरने का मार्ग, संघर्ष-विराम की शेष अवधि के लिए पूरी तरह से खुला घोषित किया जाता है।

पीएम और केरल के सीएम ने मौतों पर दुख जताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई मौतों पर गहरे दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा, तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुए हादसे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। केरल के मुख्यमंत्री पिनारायि विजयन ने भी केरल के नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। विजयन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि सभी घायल लोगों को सबसे अच्छा इलाज मिले। अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्यों की देखरेख की। घायलों को तुरंत निकालने के लिए फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया।



इसके बाद बस 9वें हैयर मोड़ पर नीचे गिर गई। बस में केरल के पेरिनथलमात्रा से आए 13 टूरिस्ट सवार थे। इन 13 लोगों में से आठ लोगों (1 पुरुष और 7 महिलाएं) की मौके पर ही मौत हो गई। पांच घायल लोगों को, जिनमें ड्राइवर, 17 से 18 साल के दो लड़के और दो महिलाएं शामिल थीं, तुरंत बचाकर पोल्हाची के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। घायलों में से एक ने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तमिलनाडु के सरकारी अधिकारियों ने इस घटना पर तुरंत कार्रवाई की। हादसे की खबर मिलते ही, दो सीनियर पुलिस